

महाराज ने अधिकारियों को चेताया

■ व्यक्तिगत रूप से लेकर हल करें समस्याओं का समाधान

देहरादून/हरिहरा। अमजन की शिकायतों का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिये जनता को कोई भी समस्या हो अधिकारी उसका निस्तारण व्यक्तिगत रूप से लेकर हल करना सुनिश्चित करें।

उक्त बात प्रमेनर आप्रम में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं और शिकायतों का मौका पर ही निस्तारण करते हुए प्रदेश के कैफियतें मंत्री एवं जिले के प्रधारी मंत्री श्री सत्याल महाराज ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा है। उन्होंने को चेतावनी देते हुए कहा कि अमजन की शिकायतों का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिये जनता की कोई भी समस्या हो, उसका निस्तारण व्यक्तिगत रूप से लेकर हल करना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लम्बा, सिंचाई, पंचांगी राश, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति जलालन प्रभावन एवं भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएं एवं जनपद प्रधारी मंत्री संपत्ति समाप्ति महाराज ने जनता दरबार कार्यक्रम में अनेक



जन-समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके लिये निस्तारण के निर्देश दिया। इस भौतिक पर महाराज ने कावड़ मेला-2022 के संक्षरण सम्पन्न होने पर सभी को बधाइ एवं शाखाकामनायें भी दी। जनता दरबार में कल 17 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर का मौका पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों को प्रकाश के निस्तारण में लगाने वाले समय के अनुरूप संबंधित विभागों को अधिकारियों के अधिकारियों

निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अगर किसी का फोन आता है, तो उसे अवश्य उड़ा लें, अब कहीं बदलता है, तो कॉल बैक जरूर करें। जनता दरबार में प्राप्त होने वाली शिकायतों में जमीन की पैमाईस, स्ट्रीट लाइट लगाया जाने, राशन कार्ड बदलने, अतिक्रमण हटाने, नाले की काफ़ी भूमि सम्बन्धी विवाद नियन्ताने, सड़क का चोड़ावरण, तटबन्ध निर्माण, रास्ता बनवाने, कच्चे माइनर को पकड़ करने, पानी की निकासी, हैंडप्यास को रिवर करने, शस्त्र लाइसेंस दिलाये जाने, वितर का केनेशन दिलाये जाने, सड़क व पुलिया निर्माण करने, नालों का निर्माण करने, आधिक सहायता दिलाये जाने, नहर की पटरी के लिये गरासा बनाने, तालाब का जांचारिया जाने, तालाब का जांचारिया विभाग, शिक्षा विभाग सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों उपस्थित थे।

शैचालयों आदि से सम्बन्धित प्रकारण प्राप्त हुए। जनता दरबार में जिलाधिकारी विवरण शब्दकार वापाड़े, अपर जिलाधिकारी पीलूल राश, एचआरएस सचिव चौहान, एसडीएस पूरन सिंह शाखाकामनायें भी दी। जनता दरबार में कल 17 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर का मौका पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों को प्रकाश के निस्तारण में लगाने वाले समय के अनुरूप संबंधित विभागों को अधिकारियों

एक नजर

उत्तराखण्ड मुक्त विधि में प्रवेश आज से शुरू

रानीखेत। उत्तराखण्ड मुक्त विधि के रानीखेत पीढ़ी कालज में संचा, लित अध्ययन केंद्र के समन्वयक डा. जेंस राश ने बताया कि उत्तराखण्ड मुक्त विधि में अप्रैल-2022 के लिये और नियन्तान के विवरण एवं अगस्त से शुरू होने वाले जारी करें। इस विधि के अधिकारी को नियन्ता के विवरण के अधिकारियों को निर्देश दिलाये जाने, नहर की पटरी के लिये गरासा बनाने, तालाब का जांचारिया विभाग, शिक्षा विभाग सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों

श्रद्धालु की गुम हुई जैवलरी को तलाश कर लौटाया अल्पांग। जांचारिया घाम में दर्शन करने के लिये उत्तराखण्ड मुक्त विधि के अधिकारी अपराधी जैवलरी में लालूली में कैंप की खो गई। जिलाधिकारी प्रधारी मेला द्वारा शुल्क देने की लालू द्वारा जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा। जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान

अल्पांग। थाना द्वारा पुलिस टीम ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर द्वारा बाला वाला में संयुक्त रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दुकानों में चिकित्सा अभियान चलाया। चिकित्सा के द्वारा दुकानदारों को किसी भी प्रकार लॉकाइट के प्रयोग के विवरण के अधिकारी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा। जैवलरी के द्वारा जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

वन आरक्षी महिला ने जहर खाकर जान दी

रामनगर। ग्राम जोगेपुर निवासी लिलिता (39) एक महिला ने अजात कारों के चलते घर में विलोप पदार्थ का संकरा के लिये राशनाकर द्वारा बाला वाला में संयुक्त रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दुकानों में चिकित्सा अभियान चलाया। चिकित्सा के द्वारा दुकानदारों को किसी भी प्रकार लॉकाइट के प्रयोग के विवरण के अधिकारी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा। जैवलरी के द्वारा जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

अल्पांग। जांचारिया घाम में दर्शन करने के लिये उत्तराखण्ड मुक्त विधि के अधिकारी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा। अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

देहरादून। अखिल भारतीय यूनानी तिक्किया को अपेक्षा की ओर से आयोजित करने के लिये एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तस्यामान सभागार में आयोजित करिकात्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आदि पर सीसीआरयूएम के पूर्व नियंत्रक डा. मुश्तक ने विस्तार से प्रकाश किया। जैवलरी के लिये गरासा बनाया जाएगा।

एक अवसर पर पर विधायक विभाग के अधिकारी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा। अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशनाकर विधि के संतोषकारी विभागों के सुधारणा एवं विवरण के अधिकारी अपराधी अपराधी जैवलरी को लालू के सुनावने के लिये गरासा बनाया जाएगा।

सुभाष चन्द्र चौधरी को सेवानिवृत्ति पर विवादी रामनगर। पीएसीए राशन

झारखंड में साजिश तो नहीं

कांग्रेस ने अपने तीन विधायकों को पार्टी से निर्लिपित कर दिया है। कांग्रेस की यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ईडी कई-कई दिन पछांत ले कर रही है। कांग्रेस ने इन विधायकों को निर्लिपित कर दिया था। तीनों झारखण्ड कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन थे। इन्हें पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने 48 लाख कैश के साथ पिरपत्तर किया था। कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई करके भाजपा को दिखाया है कि उत्तरित कार्रवाई कैसे होती है। पार्टी ने यह जाताना की कोशिश की है कि जिस भाजपा की मौजी और उसके दो लेखमुद्रे विरोधी में किए फिसकानों को गोंड डाला था। हालांकि मौजी के बेटे का तो पुलिस ने पिरपत्तर कर लिया था, लेकिन उसके मौजी पिता अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कैसे रिकवर? री के बाद झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमटी (जेपीसीसी) अध्यक्ष राजेश नाथ और आशका जाताई है कि यह झारखण्ड सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। उनका यह कहना किसी हृद तक सही भी है, क्योंकि भाजपा ने कई प्रदेशों में तोड़फोड़ कर वहाँ की सरकार को गिर दिया है। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में है। हालांकि अभी आन वाले समय में चीजें और स्पष्ट होंगी। महाराष्ट्र में पिछले महीने उद्घव टाकरे सरकार के पाने के साथ जो जगनीनक उठापुक्त समाज है। कैछ वैसी ही तब्दील झारखण्ड में भी बनान की कोशिश की जा रही है। झारखण्ड कैश कांड में एक के बाद एक नए आरोप समाजे आ रहे हैं। इस बीच झारखण्ड के एक के पारों विधायक बुमार जयमंत सिंह ने हावड़ा में पकड़े गए विधायकों का पारोपाय लगाया है। इसके साथ जयमंत सिंह ने झारखण्ड में सरकार पिरावे की साजिश और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शामिल होने की बात भी पत्र में लिखी है। दरअसल, ग्राम्पत्रिय चुनाव के बाद बगानबाबूधन खीमे में हुई क्रृषक वाटियों के बाद स ही कांग्रेस विधायकों पर शक था। झारखण्ड राज्य में कांग्रेस के 18 विधायक हैं। कांग्रेस के समर्थन से झामुकों के हमें सोने की सरकार तक रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अवनामा पांडे ने इसको लेकर पार्टी के विधायकों के साथ बन दून मीटिंग भी की थी। उहनोंने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से इस सर्वधं में रिपोर्ट सौंपें की भी पीरिंश दिया था। पांडे ने यह भी पीरिंश कहा कि क्रॉस वाटियों करने वाले बरोदी नहीं जाएंगे। हावड़ा में झारखण्ड के कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से बड़ी मात्रा में कैश मिला है, उनमें जामताड़ा के इरफान अंसारी, राची जिले के खिजरी से राजेश कंधप और सिमडंगा जिले के कालेबिरा से नमन विकसेल कांगेड़ी के नाम शामिल हैं। राजेश टाकर के विनाश में कूच सच्चिव नजर आती है, क्योंकि देश राजी दूसरी मुकाबा पर खुदा है। जहाँ 1947 में अंग्रेजों की 'बांटी' और राज 'करों' की चाल को समझने में गलती कर बैठा था, लेकिन आज देश इस चाल को जानता है, समझता है और उसका विरोध कर सकता है। आमतौर पर शासकों को सत्ता का नशा खुद के खुदा होने की गत गलतफैली का शिकायत बना देता है। उन्हें अपनी 'खुदाई' का गुमान भरने ही है। जो नियमा के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऐसे शासक बन बैठे जिसके द्वारा झटके कर करोड़ों भारतवासियों ने विश्वास किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब फिर आन (प्राचीन मिथ का ऐसा राज, जो खुद को भगवान सज्जना था) की खुदाई नहीं चली तो, ऐसे शासकों की कब कब तक चलेंगी। यह भारत है, पांचक्षान नहीं। यहाँ लोकतंत्र का राज चलता है, तानाशाह का नहीं। लोकतंत्र की कभी कभार खुदे प्रचार में बढ़ा और यह भी ही सकता है कि उसकी कभी और पांच कभी कभार धर्म की पटटी बाध दी जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस लोकतंत्र की चेताना जागृत ही न हो और उसकी आंखें न खुलें।

जान्हवी ने फिटनेस का बताया राज



311

आ मतौर पर ज्यादातर मशहूर धर्मचार्य कॉर्पोरेट जिंदगी जीते हैं। महलनुमा अत्रोंमें रहते हैं। मधुंगी गाड़ियों में धूपरेह हैं। हीरे जहारात से लदेर रहते हैं। सेकंडों करोड़ रुपये के निवेश करते हैं। अमीरों की पीछे भागत हैं और गरीबों का दिक्कारत की नजर से दखते हैं पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में मधुआरों की बस्ती में एक दिर्घि-प्रवाराम में जन्मीं अमरात्मदयी मरी एमा प्रभा एक अपवाह है। जिनका यह जीवन गरीबों की और जरुरतमंदों की सेवा के लिए ही समर्पित है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन में सुख देने वाली अमा जनसेवा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम रखने जा रही है। आगामी 24 अगस्त को फरीदाबाद में अमा के नए अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी करेंगे। 133 एकड़ भूमि में फैला ये अस्पताल भारत का सबसे यह सेख्या बिस्तरों तक पर अस्पताल का स्टाफ ते जिसमें 534 अधिक होंगे। इमेजिंग सेस और उच्च-टेक्नोलॉजी विकास का कार्डिंग का अल्टा-आप साथ भारत परियोजना न सुविधा है।

बड़ा निजी क्षेत्र का अस्पताल है। कोच्चि (केरल) में प्रतिघित 1,200 विस्तरों वाले अमृता अस्पताल के बाद यह देश में अम्मा का दुसरा बड़ा अस्पताल हो गया। केरल इस अस्पताल को 25 साल वाहने माले रात्रि अमृतानंदमठी मठ द्वारा स्थापित किया गया था। फरीदाबाद के संकट-88 में फैला यह अस्पताल 1 करोड़ वर्ग मूट का होगा, जिसमें एक 14 मंजिल ऊंची टॉवर है, जहाँ प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं की मदर से विभिन्न बीमारियों के रोगियों का इलाज होगा। अम्मा के इस अस्पताल की 81 विशिष्टताओं में न्यूरोसे, इंसरेंस, गैरूप-साइडेस, आंकोरोंजी, निलंग इन्सास, हड्डी रोग, कार्डियक साइंस और स्ट्रोक और मध्य व चक्रवृत्त जैसे उत्कृष्टताएँ के अठ कंट्रोल सायमिल होंगे। 2400 विस्तरों के लक्ष्य अस्पताल में इस साल 500 विस्तरों के साथ मरीजों का इलाज चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। आने वाले दो वर्षों में, तेजी से परिस्थिति कमरों वाला परिचारक द्वारा सेवाओं का विस्तृत करना है। मैं और अमीर फीस उसके जब राम रहने वाले आंकट इवे के लिए अब व्यक्तित्व न पूछूँगा। यह दिखाकर यह नें चलाने वाले

वॉच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का अंतिम स्तर है, लेकिन उसे पता था कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिकूल परिणाम पूरे प्रासाद के पतन को तोड़ कर दींगी। भारत के स्वॉच्च न्यायालय ने हाल के वर्षों में कई संदिग्ध निर्णय लिए हैं, लेकिन गुजरात दर्गों के लिए अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नंदेंग मोटी को जिम्मेदारी के उनके अपने हिस्से से भी बरी कर दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की अपील को खातिर कर दिए जाने का 24 जून का उकासा कैसला गुलबर्ग सोसाइटी के नरसंहार में जकिया जाफरी के पति और रिट्रेटरों की मौत की जिम्मेदारी से भी बरी कर दिया जाना उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है।

24 जून का उत्सव फैसला गुलबर्ग सोसाइटी के नक्सहार में जकिया जाफरी के पति और रिरेनेटरों की माँत की जिम्मेदारी से भी बरी कर दिया जाना उन सब में सबसे संदर्भ है।

संरिध कहना कम हो सकता है बेहतर शब्द विनाशकारी होगा। क्योंकि इस फैसले के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायशास्त्र की निष्पक्षता में नागरिक समाज के बचे-खुचे विश्वास को भी नष्ट कर दिया है। न्यायमूर्ति खानविलकर और उनके साथी न्यायधीशोंने दो न केल जकिया जाफरी की वाचिका को दो अवमननापूर्ण शब्दों-बौरे योग्यता के साथ खारिज कर दिया और इस बात को ध्यान में रखा कि मौजूदा कार्यवाही पिछले 16 वर्षों से चल रही है। यही नहीं, अपने फैसले का एक अच्छा-खासा हिस्सा उन्होंने सिटिजन फौर जरिस एंड पीस की संस्थापक और

2006 से जाफरी को सलाहकार तीसरा सूतलवाड़, गण्य खुफिया व्यारों के दो अधिकारी संजीव भट्ट और आबोदी श्रीकमार, जिनको गवाही पा श्रीमति जाफरी न्याय की तलाश में भरोसा हो थी, उन्होंना मुकदमान करने में लगाया। विद्वान् न्यायाधीश यहीं नहीं रुके। एक महत्वपूर्ण पैराग्राम में उड़न्होंने सरकार को इन तीनों पार मुकदमा चलाने के लिए एक तरह से आमंत्रित किया और जो कहा उसका मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार ने साजिश नहीं की थी, बल्कि गुजरात दोनों में मोदी को दोषी ठहराने के लिए इन तीनों में मामलों को गर्म खाने का काम किया था और ऐसा उड़न्होंने तब किया जब भट्ट और श्रीकमार मामलों में याचिकाकर्ता भी नहीं थे और याचिकाकर्ता के रूप में तीसरा को अपेक्षा अधिकारक को स्थिकीय करने से ही इकावर कर दिया। नायाक समाज के सदस्य, जो असलात में पेश भी नहीं हो रहे थे, उन पर यह हमला न करवा भारतीय बल्कि वैश्विक न्यायशास्त्र में एक मिसाल हो सकता है। इस मामले का एकमात्र चिंताजनक पहल विद्वान् न्यायाधीशों का अनर्गत दर्ज किया गया यह नियंत्रण नहीं है। फैसला 416 पन्नों का है, लेकिन गुजरात पुलिस फैसला सुनाए जाने के बाद एक

दिन के भातर सोता लवाड़ का गिरा तार करन मुबई पहुंच गई। श्रीकुमार की गिरा तारी और संजीव भट की फिर से गिरा तारी बदनाम करने के लिए है और दाक्ते लिए रह हांग कि मां अधीन करने पर गांधीजी

गर तारा, बदनाम करने का लिए ह आइसके लिए
न्यायाधीशोंगे अपने फैसले के 50 से अधिक पृष्ठ
समरपण की हैं। इसपर कार्रवाई कुछ ही घंटों में हो गई।
क्या युजरात पुलिस के वापस स्पॉड रीडर्स थे, या वह
यह फैसला सुनाए जाने से पहले किसी तरह से इसकी
एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम थी? हालांकि यह असंभव
है, केवल यह तथ्य कि संदेश मौजूद है, और आवाज
उडाई जा रही है, अविश्वास की गहराई को उत्तापन करता
है जो अब सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक समाज के
बीच विकसित हो गया है। अपनी स्वापान के बाद से यह
अभी तक यह क्षमता के व्याप्तिगत अधिकारी को रखता
कर रहा था और अन्य लोकोंमें से संवेदनशील स्वतंत्रता
तथा भारत में बढ़ती ताकत के साथ ऐसा कर रहा है,
क्योंकि पिछले आठ वर्षों में मानवीयावाद से इसे खतरा पैदा
हो गया है। तीस्ता की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, 28 जून
को, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व-न्यायाधीश मदन लोकुर ने इस
कालम में पूछा, तीस्ता सोलेलवाड को गिरफ्तार किया
जाना चाहिए यह सुधीरी कोर्ट का इरादा था या सुझाव?

अगर एसा नहीं था तो उस यह स्पष्ट करने चाहीए था, लेकिन अदालत आज तक चुप रही, जिससे इस संदेश को बढ़ा मिला कि वास्तव में इस पीठ के तीन न्यायाधीशों के मन में यही था। इसलिए, अपनी चुप्ती के माध्यम से, अदालत ने खुद को बढ़ी प्रयत्नकारिकारण के थोक विनाश के लिए एक पक्ष बना लिया है। नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है और यह कारावास जैसे दंडनीय अपराध का दोषी सावित होने तक है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है और 2014 में संघ परिवर्तन के सत्ता में आने के बाद से विशेष रूप से भारी हमले का शिकार रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनाम नीचे बैठों गिर गया है? जब से संवानिवृत्त न्यायाधीशों ने इस सरकार की पोसंद के निर्णय देने के बाद अकार्यक पदों को स्वीकार करना शुरू किया, जब से नागरिक समाज को सबसे चुंचु का सावध होने लगा है। संवाच्च न्यायालय के एक अत्यधिक सम्मानित मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवबम, को कई उल्लेखनीय फैसलों का श्रेय है। शुरूआत उन्होंने की थी जब 2014 में अदालत से हटने के 16 सप्ताह बाद करेल

त का सबसे बड़ा आय

750 विस्तरों और पांच वर्षों में 1,000 गी। गौरतलव है कि पूरी तरह से चालू होने से अधिक डॉक्टरों सहित 10,000 लोगों गए। अप्स्ट्रेलिया में तलव 2,400 बेंद होंगे, लंकेरें बेंद शामिल हैं, जो भारत में सबसे दूसरे इंडियन अपरिणाम थिएटर, सबसे उत्तनत हर तरह से स्वास्थ्यान्वयन रोबोट प्रयोगशाला, एं आंकोलांगी, सबसे आधुनिक परमाणुनिक सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय 9 वेंशेनल कैथेट तैब भी होंगे। फरीदाबाद में मन्मुता अस्पताल कम कार्बन पदचिन्ह के सबसे बड़ी ग्रीन-बिल्डिंग हृत्यक्त्यर एक होगा। यह एक एंड-टू-एंड पेपरलेस एन्यु अपरिणाम निर्वहन होता है। मरीजों के लिए परिसर में विनियोजित और एक 498 रुपये पैसे, जबां पर्सनल के माश आने का आज अम्मा की सेवाओं के काम है।

है। जल्दी नहीं कर सकता तो उसे बाजार में बेच देता है। अमाल की संस्था द्वारा चलाइ जा रही है। देशव्य दीनहीन लोगों की निःचार्य मदद उनके सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में ग्रीबीया एक जैसा लिलाज होता है। पर गरीब से न अनुसार नाम मात्र की लीजाती है। आज साराम, राधा मां, रामलला, जैसे वैष्णव में प्रमुखों का जाल बिछ चुका है, तब गीरोंवाहु लुटा देने वाली थे अमाल की साधारण कानी। आज व्यापी चैतन्यों पर स्वयं को एक मङ्गल की शिक्षा के नाम पर जादू-टोने पर मंडरा रहे खतरे बताकर, धर्म की दुक. एक लंबी कठार है। ये ऐसे धर्मपुरुह हैं,

ગુજરાત દંગોં મેં સાજિશ કી તલાશ સે નોદી બચ ગણ, અસલી દોષ નેતૃત્વ કી જિમ્નેદારી



की जानवूझकर की गई लापरवाही और इयदतन हासिल की गई विफलता को लाना चाहता हूं जिससे इस देश के निरोष नागरिकों के जान-माल को रक्षा करने में उपर नामित अभियुक्तों ने अच्छी तरह से निष्पादित और भयावह आपाराधिक साजिश रची परिणामतः 2002 के बाद से राज्य में संवैधानिक शासन दूट गया और राज्य प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था मरणीरी के दबाव में तथा उसकी व्यवस्थाएँ कात पड़ेगी करके रख्य कार्यकारिणी में सबसे शक्तिशाली द्वारा सामूहिक नरसंहार किया गया था। 62 साजिशकर्ताओं की सूची में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी थे। इस व्यापिका ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर दी, वास्तव में गंभीर न्यायिक अविवाम में से बचा जाए, जो उस स्थिति को नष्ट कर देगा जिसे अदालत ने नागरिकों के अधिकारों के अंतिम संरक्षण के रूप में बनाया था जब कार्यपालिका की कार्रवाई और विधायिका द्वारा धमकी दी गई थी। इस भूमिका को सविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया था, लेकिन अदालत द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका था और बाद के दराकों में कुछ मामलों में खात्र हो गया था। सविधान ने अनुच्छेद 132-134 और 143-144 में

पाया। वह गुजरात दंगों के पीड़ितों के साथ जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए वह जिकिया जाकरी के मामले को एक और सुनवाई से इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने नए ऐसे से जाच के उनके अनुरोध को स्वीकृत कर लिया, तो मोदी को लिए बाकी अवधिके के लिए पर घाटा देने की संभावना 1975 में इंदिरा गांधी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि कार्यपालिका अपनी न्यायालिकाको बीची आपने सामने का एक और आगे टकराव इस बार, भारत के लोकतंत्र को स्थायी रूप से समाप्त कर सकता था। यही बजह हो सकती है कि खाना विलकर बंच ने जाफरी की अपील को रसरी तौर पर खारिज कर दिया। इसमें प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके किया, न कि जांच की सामग्री पर और इसमें कोई गलती ही नहीं पायी। इस निष्कर्ष में कोई असर्चय नहीं है कि प्रक्रिया का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेन एस-आईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी कि अदालत के न्यायालिक ने रिपोर्ट की आतोचना की थी अतः अदालत ने उनकी टिप्पणियों के आलोक में रिपोर्ट को पुनरीक्षण के लिए एस-आईटी को वापस भेज दिया था। एस-आईटी ने कुछ और लागों को दोषी घटहरात हुए एक संशोधित रिपोर्ट सूचीकृत की थी, लेकिन अभियोन ने योग्यता के लिए एक नियम लाया था जिसके अनुसार एस-आईटी को वापस भेजने की जिम्मेदारी नहीं थी। एस-आईटी को वापस भेजने की जिम्मेदारी नहीं थी।

सबूत का कमा के लिए मादा का सामुक्त हानि को पुरा की थी। बंदे ने अखिकारा इसे सही ठहराया। दूसरे फैसले का शायद ही क्षेत्रीय महत्व होता है, परन्तु फैसले किए जाने होते हैं जो कोटिक 2002 में जो आपाध्य हुआ वह तेजी से दो हिस्सों में बंट रहे हमारे सम्प्रदायिक अधिकारों को अनुप्राप्त दी, जिनमें सामान्य महत्व के कानूनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था और आपाधिक मामलों में अगर एक उच्च न्यायालय ने अपील पर, एक आरोपी को बरी करने के आदेश को उलट दिया और उसे मौत की सजा मुनाफ़ा या अधीनस्थ अदालत को सिसी भी मामले को सुनवाई के लिए वापस ले लिया था। ये अधिकार प्रतिवर्धात्मक धाराएं थीं, लेकिन उनकी पांचभारी को एक ऐसी धारा के समक कर दिया गया था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुप्राप्त देने की अनुप्राप्त दी थी, यदि वह संपृष्ठ था कि एक मामले में इसकी आवश्यकता है। यह इस अंतिम, सर्वधारणी अनुप्राप्त के तहत था कि इसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भूमिका ग्रहण की थी, जोक्या भारतीय लोकतंत्र की कामयास समने आने लगी थीं। इस प्रवाधन के तहत इसके फैसले ने अदालत को कानून के मुद्दों पर अंतिम अपील की अदालत से बदल दिया, जो अमातृर पर केवल अमीर और शक्तिशाली को लिए साथी, अधिकारों और अनुप्राप्तता के लिए साथी थी गई है।

केंद्र में शीर्ष पर भाजपा के सत्ता में आने के साथ, नागरिकों के अधिकारों का हनन सामान्य हो गया, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की खाड़ी तेजी से चोड़ी हो गई। 2017 में जकिया जाफरी की सुधीमी कोर्ट में अपील ने इसे अतुलीय बना दिया जोक्या इसके मुख्य आरोपी अब भारत के प्रधानमंत्री थे। इसने सर्वोच्च न्यायालय को एक असंभव स्थिति में डाल दिया जानी चाहिए कि पर न करने से न्यायपालिका के अपने अधिकारों की संरक्षकता में जनता का विश्वास और कम हो जाता, लेकिन मामले को फिर से खोलने से संवेदनाक असंकेत पैदा हो जाएगा। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति उनके फैसले से जो खुला चिन्हप्रदर्शित होता है, वह उस स्थिति के साथ उनकी अपीलों पर विचार करने की अनुप्राप्त दी, जिनमें सामान्य महत्व के कानूनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था और आपाधिक मामलों में अगर एक उच्च न्यायालय ने अपील पर, एक आरोपी को बरी करने के आदेश को उलट दिया और उसे मौत की सजा मुनाफ़ा या अधीनस्थ अदालत को सिसी भी मामले को सुनवाई के लिए वापस ले लिया था। ये अधिकार प्रतिवर्धात्मक धाराएं थीं, लेकिन उनकी पांचभारी को एक ऐसी धारा के समक कर दिया गया था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुप्राप्त देने की अनुप्राप्त दी थी, यदि वह संपृष्ठ था कि एक मामले में इसकी आवश्यकता है। यह इस अंतिम, सर्वधारणी अनुप्राप्त के तहत था कि इसने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भूमिका ग्रहण की थी, जोक्या भारतीय लोकतंत्र की कामयास समने आने लगी थीं। इस प्रवाधन के तहत इसके फैसले ने अदालत को कानून के मुद्दों पर अंतिम अपील की अदालत से बदल दिया, जो अमातृर पर केवल अमीर और शक्तिशाली को लिए साथी, अधिकारों और अनुप्राप्तता के लिए साथी थी गई है।

केंद्र में शीर्ष पर भाजपा के सत्ता में आने के साथ, नागरिकों के अधिकारों का हनन सामान्य हो गया, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की खाड़ी तेजी से चोड़ी हो गई। 2017 में जकिया जाफरी की सुधीमी कोर्ट में अपील ने इसे अतुलीय बना दिया जोक्या इसके मुख्य आरोपी अब भारत के प्रधानमंत्री थे। इसने सर्वोच्च न्यायालय को एक असंभव स्थिति में डाल दिया जानी चाहिए कि पर न करने से न्यायपालिका के अपने अधिकारों की संरक्षकता में जनता का विश्वास और कम हो जाता, लेकिन मामले को फिर से खोलने से संवेदनाक असंकेत पैदा हो जाएगा। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति उनके फैसले से जो खुला चिन्हप्रदर्शित होता है, वह उस स्थिति के साथ उनकी अपीलों पर विचार करने के लिए सुनिश्चित स्टॉइकिंग फॉरम्यूला (हमलावर सेना) थी। वह अवसर चुक गया है और उन्हींने लौटेगा जब मोदी और भाजपा सत्ता में नहीं होंगे।

...प्रेम शंकर झा

(लेखक चरित्प्रसाद कामान)

गर अत्यधिक बेचैनी को दर्शाता है जिसमें उन्होंने खुद को एवं सामाजिक चिंतक हैं।

अम्मा ने बनाया भारत का सबसे बड़ा अस्पताल



की जाती थी। उनके बाकी भाई-बहिनों को खूब प्रशंसा किया गया, पर अमा केवल चौथी पास रह गई। इन विपरीत परिस्थितियों में भी अमा ने कृपा प्रवित और मां कलो की धूमधारी रूपी रूपी थी। इनकी तीव्रता से दिन-रात जगन रखने की उनकी साधना सिद्ध हो गई। कलंगुरु के लोगों चमकार देखना चाहते हैं, पर अमा स्वयं को सेविका बताकर चमकार दिखाने से बचती रही है। पर ये चमकार क्या कर मैं हूँ कि वे आज तक दुनियाभर में जाकर 5 करोड़ से अधिक लोगों को गले लगाए चुकी हैं। उनको सत्त्वना दे चुकी हैं, उनके दुख हर चुकी हैं और उन्हें सदमग्रण पर चरने के लिए प्रेरित करती रही हैं। इसके चमकार के बावजूद हमारी ब्राह्मणावादी हृदय व्यवस्था ने एक महान् तात्त्विकों को मछुआना मानकर वे सम्मान नहीं दिया, वे सत् समाज में उन्हें दिया जाना चाहिए था। ये बात दुसरी है कि दौंगी गुरुओं के मायाजाल के बावजूद दुनियाभर के तमाम पढ़े-लिखे लोग, वैज्ञानिक, सफल व्यवसायी, सिने कलाकार,



विद्यावाचा

नेता और पत्रकार भारी मात्रा में उनके शिय्य बन चुके हैं औं औं उनके आगे बालों की तरह बिलख-बिलख कर अपने दुख बताते हैं। मां सबको अपने ममतामयी अलिंगन से रहात प्रवास करती हैं। उनके आचरण में न तो वैधव का प्रसरण है औं न ही अपनी विश्ववाच्यामी को अंहकर। जबकि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की सोकसें बड़ी सम्मानित संस हैं। उनके द्वारा पत्रकों भी, कम्ही भी, अपनी फरियाद लेकर जा सकता है।

